

एलईडी को प्रोत्साहन की मांग, 21,000 मेगावाट बिजली की बचत संभव

नई दिल्ली, (भाषा)। देश में सामान्य बल्ब, ट्यूबलाइट अथवा सीएफएल के स्थान पर एलईडी तकनीक वाले बल्ब के इस्तेमाल से 21,000 मेगावाट से अधिक बिजली बचाई जा सकती है पर इस उद्योग के लोगों का कहना है ये बल्ब महंगे होने से भी इनके इस्तेमाल में अपेक्षित तेजी नहीं आ सकी है। एलईडी उद्योग का कहना है कि सरकार को रोशनी के इस किफायती स्रोत को प्रोत्साहित करने के लिए देश में इस उद्योग को अधिक मदद करनी चाहिए। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डियोड उत्पाद बनाने वाली एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक अरुण गुप्ता ने 'भाषा' से बातचीत में कहा, "अभी देश में एलईडी की मांग कम है, इस लिहाज से विनिर्माण भी सीमित है तथा लागत भी ऊंची बैठती है। जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और लागत भी नीचे आएगी।" उन्होंने कहा कि यूरोप में ऊंचे वॉट वाले इन्कन्डेसंट बल्बों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कम वाट वाले बल्बों को भी हटाया जा रहा है। समूचा यूरोप धीरे-धीरे एलईडी की ओर रुख कर रहा है। इसी तरह जापान ने 2011 में सुनामी के बाद 2020 तक पूरी तरह एलईडी बल्ब के इस्तेमाल का लक्ष्य रखा है।

ऐसे में भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में एलईडी का इस्तेमाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। गुप्ता ने कहा कि एलईडी के इस्तेमाल से औसतन 60 फीसद बिजली बचाई जा सकती है और भारत में यह बचत 21,000 मेगावाट से अधिक की हो सकती है। उन्होंने कहा एक मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता खड़ी करने की लागत यदि 5 करोड़ रुपये मान लें तो इस लिहाज से एलईडी इस्तेमाल से होने वाली बचत का मूल्य 1.05 लाख करोड़ रुपये तक बैठता है। एलईडी उद्योग के लोगों का कहना है कि कंपनियां अब एलईडी अपनाने लगी हैं। कई बड़ी कंपनियों के कार्यालयों में अब एलईडी बल्ब दिखने लगे हैं।

गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी एलईडी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन राज्यों में सरकारी इमारतों में एलईडी लगाई जा रही है। देश में 31 मार्च, 2012 तक बिजली की कुल स्थापित क्षमता 2.36 लाख मेगावाट थी। टेरी तथा अन्य उद्योग सूत्रों के अनुसार किसी भी विकासशील देश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता में से 15 फीसद का इस्तेमाल रोशनी के लिये होता है। हालांकि, एनटीएल इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रबंध निदेशक गुप्ता इस

बात को मानते हैं कि एलईडी की कीमत ऊंची है, लेकिन 25,000 घंटे के इसके जीवनकाल को देखते हुए इसे 'महंगा' नहीं कहा जा सकता। फॉस्ट एंड सुलिवन के अनुमान के अनुसार भारत का एलईडी लाइटिंग बाजार 14.3 करोड़ डालर का है जो कुल लाइटिंग बाजार का 4 फीसद है। 2018 तक यह बढ़कर 1.3 अरब डालर हो जाएगा, यह कुल लाइटिंग बाजार का 15 से 20 फीसद होगा। फिलहाल देश के एलईडी बाजार के 80 फीसद पर चीन का कब्जा है, जबकि ब्रांडेड की हिस्सेदारी 20 फीसद है। गुप्ता ने कहा, "सरकार को रोशनी के इस स्रोत को प्रोत्साहित करने के लिए राहत देनी चाहिए। साथ ही इसके प्रति लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है।" गुप्ता ने कहा कि देश के खुदरा, हॉस्पिटैलिटी व स्वास्थ्य सेवा ऐसे क्षेत्र हैं, जहां एलईडी के लिए काफी संभावनाएं हैं। एनटीएल के देश में सात विनिर्माण संयंत्र नोएडा, देहरादून व रूड़की में हैं। इन संयंत्रों की मासिक उत्पादन क्षमता डेढ़ करोड़ इकाई की है। गुप्ता ने कहा कि यदि मांग में अधिक तेजी से इजाफा होता है, तो कंपनी एक और संयंत्र की संभावना पर विचार कर सकती है।